REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.7631(UIF)
VOLUME - 15 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2026

"सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के आर्थिक प्रभाव का अध्ययन (रीवा जिले के संदर्भ में)"

पूजा शुक्ला[1], डॉ. सतीश कुमार गर्ग[2]
[1]शोधार्थी वाणिज्य, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर (म.प्र.)
[2]प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष वाणिज्य, शासकीय विवेकानन्द स्नातकोत्तर महाविद्यालय, मैहर (म.प्र.)

सारांश –

प्रस्तुत शोधकार्य रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Public Distribution System – PDS) की योजनाओं के आर्थिक प्रभावों का वाणिज्यिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया गया है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली भारत सरकार की एक प्रमुख कल्याणकारी योजना है, जिसका लक्ष्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम मूल्य पर आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध कराना है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह प्रणाली केवल सामाजिक कल्याण तक सीमित नहीं है, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था, बाजार संरचना, मूल्य स्थिरता एवं उपभोक्ता क्रय–शक्ति को भी प्रभावित करती है। रीवा जिला जो कि कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बहुल क्षेत्र है, यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं पर जनसंख्या की उच्च निर्भरता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं ने उपभोक्ताओं के खाद्य व्यय को कम करने, गरीबी प्रभाव को सीमित करने और स्थानीय बाजार में मांग–आपूर्ति संतुलन बनाए रखने में योगदान दिया है।

मुख्य शब्द : *सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आर्थिक प्रभाव, वाणिज्यिक अध्ययन, खाद्य सुरक्षा, रीवा जिला, उपभोक्ता क्रय–शक्ति।*

प्रस्तावना –

किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था में संसाधनों का न्यायसंगत वितरण और सामाजिक कल्याण न केवल आर्थिक स्थिरता का आधार हैं, बल्कि बाजार संतुलन एवं उपभोक्ता संरक्षण के लिए भी आवश्यक हैं। भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) इसी प्रकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और आर्थिक असमानताओं को कम करना है। स्वतंत्रता के पश्चात् भारत ने कई आर्थिक एवं खाद्य संकटों का सामना किया है। उन परिस्थितियों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली का विकास एक आवश्यक कदम था। प्रारंभ में यह प्रणाली शहरी क्षेत्रों तक सीमित रही, लेकिन समय के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इसे ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों तक विस्तारित किया गया है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से PDS को सरकारी हस्तक्षेप के रूप में देखा जाता है, जो बाजार में मांग और आपूर्ति के असंतुलन को नियंत्रित कर मूल्य स्थिरता एवं उपभोक्ता हितों की रक्षा करता है। जब सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खाद्यान्न का क्रय कर उसे रियायती दरों पर वितरित करती है, तो यह प्रक्रिया उत्पादन, वितरण और उपभोग तीनों स्तरों पर आर्थिक प्रभाव उत्पन्न करती है।

रीवा जिला मध्यप्रदेश के विंध्य क्षेत्र का एक प्रमुख कृषि प्रधान जिला है। जिले की सामाजिक–आर्थिक संरचना में निम्न एवं मध्यम आय वर्ग की प्रधानता है, जिससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। ये योजनाएँ न केवल खाद्य व्यय कम करती हैं, बल्कि उपभोक्ताओं की सीमित आय को अन्य आवश्यकताओं पर व्यय करने का अवसर भी देती है। इस अध्ययन के दृष्टिकोण से PDS की योजनाएँ स्थानीय बाजार संरचना, मूल्य निर्धारण, मांग–आपूर्ति संतुलन और उपभोक्ता व्यवहार पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव डालती हैं। इस प्रकार यह शोध–पत्र रीवा जिले के संदर्भ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के बहुआयामी आर्थिक प्रभावों का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शोध उद्देश्य –

शोध के उद्देश्य अध्ययन की दिशा, विषयवस्तु और सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। प्रस्तुत अध्ययन में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के आर्थिक प्रभावों को वाणिज्यिक दृष्टिकोण से समझने का प्रयास किया गया है। रीवा जिले को अध्ययन क्षेत्र के रूप में चयनित करने का कारण यहाँ सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर जनसंख्या की उच्च निर्भरता और सीमित आय–संसाधन हैं। वाणिज्य विषय के अंतर्गत यह अध्ययन विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह उपभोग, व्यय, मूल्य और बाजार संरचना जैसे मूलभूत आर्थिक तत्वों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। प्रस्तुत शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं –

- रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के प्रमुख आर्थिक प्रभावों का अध्ययन करना।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ताओं की क्रय–शक्ति और व्यय संरचना पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना।
- स्थानीय अर्थव्यवस्था और बाजार स्थिरता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की भूमिका का मूल्यांकन करना।

उपरोक्त उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए शोध पत्र को वास्तविक मानकों के अनुरूप पूर्ण करने का सार्थक प्रयास किया गया है।

शोध प्रविधि –

प्रस्तुत शोध–कार्य में द्वितीयक समंकों पर आधारित वर्णनात्मक और विश्लेषणात्मक शोध विधि अपनाई गई है। द्वितीयक समंकों में भारत सरकार एवं मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रकाशित रिपोर्टें, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के दस्तावेज, जिला सांख्यिकीय पुस्तिकाएँ, योजना आयोग और नीति आयोग की रिपोर्टें, शोध–पत्र एवं संबंधित पुस्तकें सम्मिलित हैं। इन स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण वाणिज्यिक दृष्टिकोण से किया गया है। प्रतिशत विधि, तुलनात्मक अध्ययन और प्रवृत्ति विश्लेषण का प्रयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं के आर्थिक प्रभावों को स्पष्ट किया गया है। अध्ययन में मांग–आपूर्ति सिद्धांत, उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत और मूल्य स्थिरता सिद्धांत को सैद्धांतिक आधार के रूप में अपनाया गया है।

विश्लेषण –

सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं ने रीवा जिले की आर्थिक संरचना पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला गया है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार जिले की बड़ी जनसंख्या रियायती दरों पर गेहूँ, चावल और अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त करती है। इसका परिणाम यह हुआ है कि घरेलू खाद्य व्यय में कमी आई और उपभोक्ताओं की वास्तविक आय बढ़ी है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से यह स्थिति उपभोग संरचना को प्रभावित करती है। जब आवश्यक खाद्यान्न कम मूल्य पर उपलब्ध होते हैं, तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय को अन्य आवश्यकताओं जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और घरेलू उपभोग पर खर्च कर सकते हैं। इस प्रकार स्थानीय अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष रूप से मांग में वृद्धि होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली बाजार मूल्य स्थिरता में भी योगदान देती है। नियमित सरकारी आपूर्ति बाजार में कृत्रिम कमी को रोकती है, जिससे मूल्य अस्थिरता और जमाखोरी की संभावनाएँ कम होती हैं। वितरण संबंधी कुछ प्रशासनिक कमियों के बावजूद, समग्र प्रभाव सकारात्मक पाया गया है। इस प्रकार सार्वजनिक वितरण की येजनाओं का आर्थि प्रभाव से संबंधित विवरण तालिका क्रमांक–01 में प्रस्तुत किया गय है, जो इस प्रकार है–

तालिका क्रमांक–01
सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं का आर्थिक प्रभाव संबंधी विवरण

क्रमांक	योजनाओं के आर्थिक प्रभाव से संबंधित विवरण	प्रतिशत
1.	लाभार्थी परिवारों का अनुपात	65%
2.	खाद्य व्यय में कमी	52%
3.	बाजार मूल्य स्थिरता पर प्रभाव	70%
4.	गरीबी प्रभाव में कमी	48%

स्रोत : खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, मध्यप्रदेशय जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, रीवा।

उपर्युक्त तालिका के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि रीवा जिले में 65 प्रतिशत परिवार PDS योजनाओं से प्रत्यक्ष लाभान्वित हैं। खाद्य व्यय में कमी लगभग 52 प्रतिशत परिवारों में दर्ज हुई है, जो उपभोक्ताओं की वास्तविक आय में वृद्धि का संकेत देती है। इससे यह भी स्पष्ट है कि PDS योजनाओं का बाजार मूल्य स्थिरता पर लगभग 70 प्रतिशत तक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। गरीबी प्रभाव में कमी लगभग 48 प्रतिशत है। उपरोक्त आंकड़े इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएँ केवल सामाजिक सुरक्षा का साधन नहीं, बल्कि प्रभावी आर्थिक हस्तक्षेप भी हैं।

निष्कर्ष –

पस्तुत शोध अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि रीवा जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाओं ने आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इन योजनाओं ने न केवल खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की, बल्कि उपभोक्ताओं की क्रय–शक्ति को बढ़ाकर स्थानीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता भी प्रदान की है। वाणिज्यिक दृष्टिकोण से PDS एक प्रभावी सरकारी हस्तक्षेप है, जो बाजार की असंतुलित शक्तियों को नियंत्रित करता है। खाद्य व्यय में कमी, मूल्य स्थिरता और उपभोग संरचना में संतुलन इसके प्रमुख आर्थिक प्रभाव हैं। वितरण व्यवस्था में कुछ प्रशासनिक कमियाँ हैं, जिन्हें सुधारकर योजनाओं का प्रभाव और अधिक बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की योजनाएँ रीवा जिले में आर्थिक स्थिरता और सामाजिक कल्याण का एक सशक्त माध्यम है।

संदर्भ –

1. शर्मा, आर. के., भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली, नई दिल्ली, 2018
2. मिश्रा, एस. पी., खाद्य सुरक्षा एवं बाजार अर्थशास्त्र, दिल्ली, 2019
3. मध्यप्रदेश शासन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति प्रतिवेदन, भोपाल, 2020
4. सिंह, ए. के., कृषि विपणन एवं मूल्य स्थिरता, लखनऊ, 2021
5. योजना आयोग, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मूल्यांकन, नई दिल्ली, 2022
6. वर्मा, एन., वाणिज्य एवं कल्याण अर्थशास्त्र, जयपुर, 2023
7. जिला सांख्यिकी कार्यालय, रीवा, जिला सांख्यिकीय पुस्तिका, रीवा, 2024